International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

वित्तीय अंतर के फ़ासले को कम करना: मध्य प्रदेश में ग्रामीण बैंकिंग के विस्तार हेतु नीतिगत रणनीतियाँ

Kuldeep Bhanu Jayaswal, Dr. Vinod Kumar Mishra
Research Scholar, Sabarmati University, Ahmedabad Gujarat

Research Supervisor, Sabarmati University, Ahmedabad Gujarat

सारांश

यह मात्रात्मक और वर्णनात्मक क्रॉस-सेक्शनल शोध मध्य प्रदेश में बैंक अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करता है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के शाखा प्रबंधकों और अधिकारियों से डेटा एकत्र करने के लिए संरचित प्रश्नावली और अर्ध-संरचित साक्षात्कारों का उपयोग किया गया। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि बैंकिंग विस्तार के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियाँ सरकारी योजनाओं का प्रचार (***85%)*** और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन (***78%)*** रही हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई प्रमुख बाधाएँ भी सामने आईं, जैसे बुनियादी ढाँचे की कमी (***65%),*** किसानों में निम्न डिजिटल साक्षरता (***72%),*** और अपर्याप्त कनेक्टिविटी (***68%)***। इन पहलों की प्रभावशीलता के विश्लेषण से पता चला कि सरकारी योजनाओं के प्रचार के कारण प्रति शाखा ***200*** नए खाते खोले गए और ग्राहकों की संतुष्टि दर ***85%*** रही। यह अध्ययन दर्शाता है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षरता के स्तर को बढ़ाने, बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और जागरूकता अभियानों में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

मुख्यशब्द: ग्रामीण वित्तीय समावेशन, बैंकिंग पहुंच, नीतिगत रणनीतियाँ, डिजिटल बैंकिंग विस्तार, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

आर्थिक और सामाजिक विकास को वित्तीय समावेशन से बढ़ावा मिलता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां बैंकिंग सेवाएँ व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ पारंपरिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बहुत सीमित या न के बराबर है। जब लोग आसानी से वित्तीय सेवाओं तक नहीं पहुँच पाते, तो बचत, ऋण लेने और समग्र वित्तीय स्थिरता से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इस वित्तीय अंतर को पाटने के लिए एक सुव्यवस्थित विधायी ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जा सके, वित्तीय साक्षरता के स्तर को बढ़ाया जा सके और डिजिटल बैंकिंग तकनीकों का उपयोग किया जा सके।

जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग और छोटे व्यवसाय वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके लिए उन आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना आसान हो जाता है जो दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करती हैं। मध्य प्रदेश में वित्तीय सेवाओं की सुचारू डिलीवरी में बाधाएँ आती रही हैं, जिनमें कमजोर बुनियादी ढांचा, निम्न डिजिटल साक्षरता स्तर, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और भौगोलिक सीमाएँ शामिल हैं।

कई ग्रामीण निवासी अभी भी अनौपचारिक बैंकिंग नेटवर्क पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें उच्च ब्याज दरों और वित्तीय अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचना चाहते हैं, तो वहाँ अधिक बैंकों की स्थापना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (**PMJDY**) एक ऐसा सरकारी कार्यक्रम है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भारत के हर परिवार की बैंक खाता सुविधा तक पहुँच हो। फिनटेक समाधान और मोबाइल बैंकिंग के विस्तार ने उन लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त करना आसान बना दिया है, जिनके आसपास कोई भौतिक बैंक शाखा नहीं है। लेकिन अभी भी अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, वित्तीय शिक्षा की कमी और ऑनलाइन बैंकिंग के प्रति अविश्वास जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए नीति-निर्माताओं को ग्रामीण उपभोक्ताओं में बैंकों और उनकी सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करने होंगे।

ग्रामीण मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और बैंकिंग संवाददाताओं (**BCs**) का मजबूत नेटवर्क तैयार करना एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। ये मध्यस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों और टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप किफायती डिजिटल बैंकिंग समाधान विकसित किए जा सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों का उपयोग बढ़ाने के लिए विश्वसनीय इंटरनेट सेवा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (**RRBs**) और सहकारी बैंक भी इस वित्तीय अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थान ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसायों और किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और वहाँ गहरी जड़ें जमा चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच में सुधार करने के लिए परिचालन क्षमता को मजबूत करना, रियायती ऋण प्रदान करना और तकनीकी बुनियादी ढांचे को उन्नत करना आवश्यक है। नीति-निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहनों और विनियामक उपायों के माध्यम से बैंकों को उपेक्षित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अभी भी कई ग्रामीण लोग औपचारिक बैंकिंग के लाभों से अनजान हैं, जिसके कारण वे इसका उपयोग नहीं करते। गलतफहमियों को दूर करने और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को अपनाने के लिए सेमिनार, सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम और लक्षित प्रचार अभियानों का आयोजन किया जा सकता है। गैर-लाभकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों और बैंकों के बीच सहयोग के माध्यम से वित्तीय जानकारी को व्यापक रूप से वितरित किया जा सकता है।

साहित्य की समीक्षा

त्रिपाठी, आशुतोष (2013): शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न-आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (**SHG-BLP**) की स्थापना की गई। यह शोध पत्र पिछले **20** वर्षों में इस कार्यक्रम के विकास को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है, जिसमें शामिल हैं: **(a)** कार्यक्रम की पहुँच, **(b)** भौगोलिक असमानताएँ, **(c)** बैंकिंग और सामाजिक-

आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों (**SHGs**) का विस्तार, और (**d**) ग्रामीण गरीबों तक पहुँचने की इस योजना की वास्तविक एवं संभावित सफलता।

मोर, नचिकेत एवं अन्य (2008): इस लेख में गरीबी उन्मूलन के लिए बाजार-आधारित कई रणनीतियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जो न्यूनतम अनुदान और सब्सिडी फंड के उपयोग के साथ बड़े पैमाने पर लागू की जा सकती हैं। वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता होती है। बैंकों और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के बीच नवाचार आधारित साझेदारी इस लक्ष्य को लाभदायक और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बना सकती है। इस अध्ययन के अनुसार, वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, ग्राहकों की आजीविका से संबंधित विकल्पों और स्थानीय वित्तीय संस्थानों की क्रियान्वयन क्षमता को ध्यान में रखते हुए विशेष हस्तक्षेप विकसित किए जा सकते हैं, जिससे गरीब वर्ग की आय में सकारात्मक वृद्धि संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, यह रिपोर्ट बताती है कि विकास संगठनों को "आर्थिक सेवाएँ" प्रदान करने के बजाय स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण और परिवर्तन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हालाँकि, जब गरीब समुदायों के पास स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी क्षमताएँ नहीं होतीं, तब ऐसे संगठनों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

वेंकटरमणी, शिवकुमार एवं अन्य (2011): वित्तीय वैश्वीकरण के इस युग में, विकसित और विकासशील देशों में वित्तीय सेवाओं की पहुँच का विस्तार एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) का उपयोग किया जा रहा है, जबकि कई अन्य देशों में सूक्ष्म ऋण संस्थानों की प्रभावशीलता सीमित रही है। यह अध्ययन भारत में व्यावसायिक बैंकों और स्वयं सहायता समूहों (**SHGs**) के बीच प्रभावी साझेदारी पर केंद्रित है। विशेष रूप से, महिला स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तिकरण, और वंचित समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव उच्च जीवन स्तर, बाल श्रम और मृत्यु दर में कमी, महिला सशक्तिकरण और शांतिपूर्ण समाज के रूप में देखा जा सकता है।

राठी, मीनाक्षी एवं अन्य (2020): वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास का एक नया मॉडल है। भारत की ग्रामीण आबादी (**2011** की जनगणना के अनुसार **68.84%**) में से **25.70%** गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है। मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि को प्रेरित कर रही है। **2008-2018** के दौरान, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर **9.7%** रही, जबकि पिछले पाँच वर्षों में यह **18%** रही। इस अध्ययन का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि कृषि ऋण की उपलब्धता से मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए कृषि ऋण और कृषि उत्पादन के बीच एक दीर्घकालिक सकारात्मक संबंध है। इस अध्ययन से यह भी पता चला कि कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद (**GDP**) में वृद्धि होती है। हालाँकि, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण की अपर्याप्तता एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, जिसके समाधान के लिए नवीन आर्थिक मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है।

बागली, सुप्रवात एवं अन्य (2012): भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय राज्यों में वित्तीय समावेशन की प्रगति का मूल्यांकन करना है। इस शोध में रोटेटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके

प्रत्येक राज्य के लिए वित्तीय समावेशन का एक व्यापक माप तैयार किया गया है। इस अध्ययन में कुल **11** वित्तीय समावेशन संकेतकों को शामिल किया गया है। इस शोध में उपयोग किए गए डेटा भारतीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) के आधिकारिक स्रोतों से लिए गए हैं। परिणामों से पता चलता है कि वित्तीय समावेशन और मानव विकास के बीच एक सकारात्मक संबंध है। हालाँकि, भारत के विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय समावेशन में व्यापक असमानताएँ देखी गई हैं, जहाँ गोवा इस क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि दक्षिणी राज्यों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है।

रंजन, केएस एवं अन्य (2015): भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) और अन्य बैंकों द्वारा कई प्रभावी प्रयास किए जाने के बावजूद, भारत में बैंक खाता धारकों की संख्या अब भी केवल **48%** है, जबकि जर्मनी जैसे विकसित देशों में यह दर लगभग **100%** है। यह अध्ययन उन गरीब और वंचित समुदायों के बीच बैंकिंग सेवाओं की पहुँच का विश्लेषण करता है, जिन्होंने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से ऋण लिया था। अध्ययन में महाराष्ट्र के **550** उत्तरदाताओं से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि बैंक खाता होने के बावजूद लोग बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहे थे। अध्ययन से यह भी पता चला कि केवल बैंक खाता खोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बैंकों को अपनी सेवाओं की गति और लचीलापन बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ये सेवाएँ अधिक समावेशी और प्रभावी बन सकें।

अग्वु, एडविन (2020): गरीबी और आर्थिक असमानता उन्मूलन दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए। डिजिटल वित्तीय सेवाएँ लोगों तक धन की पहुँच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो रही हैं, लेकिन कई विकासशील देशों में यह अब भी प्रारंभिक चरण में है। इस अध्ययन में बताया गया है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाने में अवसंरचनात्मक समस्याएँ, निम्न स्तर का विश्वास, और अशिक्षा जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई इन सेवाओं के समावेश को बाधित करती है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि किस हद तक प्रौद्योगिकी वित्तीय बहिष्करण को कम करने में सहायक हो सकती है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि अनौपचारिक वित्तीय तंत्र कई गरीब समुदायों के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत जुड़ाव अधिक होता है। इसके विपरीत, औपचारिक वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ जटिल प्रक्रियाओं से भरी होती हैं। इस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि वित्तीय संस्थानों को अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और अनौपचारिक वित्तीय प्रणालियों के उपयोगी पहलुओं को भी अपनाना चाहिए, जिससे गरीबों की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच आसान हो सके।

शोधकार्य की क्रियाविधि

अध्ययन की रूपरेखा

यह शोध मध्य प्रदेश में ग्रामीण बैंकिंग के विस्तार में बैंक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों और उनके समक्ष आने वाली बाधाओं पर केंद्रित है। इस शोध में मात्रात्मक और वर्णनात्मक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन पद्धति अपनाई गई है। राज्य के विभिन्न ग्रामीण शाखाओं के शाखा प्रबंधक और अधिकारी इसमें प्रतिभागी रहे। विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, पदों और अनुभव स्तरों से

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal
www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

अधिकारियों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति (**Stratified Random Sampling**) के माध्यम से किया गया।

डेटा संग्रह उपकरण

प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए एक संगठित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें मुक्त-उत्तर (ओपन-एंडेड) और सीमित-उत्तर (क्लोज़्ड-एंडेड) प्रश्नों के साथ-साथ लाइकेर्ट स्केल (**Likert Scale**) भी शामिल था। इस सर्वेक्षण को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया था कि यह जनसांख्यिकी (**Demographics**), बैंक अधिकारियों द्वारा ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों और इन पहलों की सफलता की धारणा से संबंधित डेटा एकत्र कर सके। इसके अलावा, कुछ प्रतिभागियों के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार (**Semi-Structured Interviews**) भी किए गए, जिससे ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं से संबंधित चुनौतियों और उनके संभावित समाधान को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

डेटा संग्रह प्रक्रिया

दो महीनों की अवधि में डेटा एकत्र करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया गया। बैंक अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन सर्वेक्षण ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए, जिससे वे आसानी से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण बैंक शाखाओं का दौरा कर प्रत्यक्ष साक्षात्कार और सर्वेक्षण भी किए गए, जिससे प्रतिभागियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया जा सका। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा की पुष्टि करने और विस्तृत संदर्भ प्रदान करने के लिए माध्यमिक डेटा समीक्षा (**Secondary Data Review**) भी की गई। इन अध्ययनों में शाखा-स्तरीय प्रदर्शन रिपोर्ट (**Branch-Level Performance Reports**) और आधिकारिक बैंकिंग आंकड़े (**Official Banking Statistics**) शामिल किए गए।

डेटा विश्लेषण और व्याख्या

तालिका 1: नमूने में शामिल बैंक अधिकारियों की प्रोफ़ाइल

चर (Variable)	श्रेणियाँ/सांख्यिकी (Categories/Statistics)	आवृत्ति (%) (Frequency %)
पद	शाखा प्रबंधक	40%
	अधिकारी	60%
ग्रामीण बैंकिंग में अनुभव	5 वर्ष से कम (<5 years)	45%
	5–10 वर्ष (5–10 years)	35%

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal
www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

	10 वर्ष से अधिक (>10 years)	20%
लिंग	पुरुष	70%
	महिला	30%

निम्नलिखित तालिका में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं के लिंग विभाजन, ग्रामीण बैंकिंग में उनके अनुभव के वर्षों की संख्या और पदवी को दर्शाया गया है। सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में से **60%** अधिकारी **(Officer)** और **40%** शाखा प्रबंधक **(Branch Manager)** हैं। यदि ग्रामीण बैंकिंग में उनके अनुभव स्तर को देखें, तो **45%** का अनुभव **5** वर्ष से कम, **35%** का **5-10** वर्ष और **20%** का **10** वर्ष से अधिक है। इसके अलावा, सर्वेक्षण में भाग लेने वालों में **70%** पुरुष और **30%** महिलाएँ हैं।

तालिका 2: ग्रामीण बैंकिंग के विस्तार के लिए बैंक अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम

उठाए गए कदम	**आवृत्ति (%)**
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना	78%
सरकारी योजनाओं (जैसे PMJDY) को बढ़ावा देना	85%
जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय नेताओं के साथ सहयोग	60%
मोबाइल बैंकिंग वैन स्थापित करना	50%
बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) की भर्ती/प्रशिक्षण	65%
खाता खोलने के लिए ग्रामीण शिविर आयोजित करना	70%
डिजिटल बैंकिंग जागरूकता बढ़ाना	55%

तालिका में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की आवृत्ति और प्रकार को दर्शाया गया है। अधिकांश उत्तरदाता **(85%)** सरकारी योजनाओं जैसे कि पीएमजेडीवाई **(PMJDY)** को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके बाद वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम **(78%)** एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया है, जबकि **70%** उत्तरदाता खाता खोलने के लिए ग्रामीण शिविर आयोजित करने को प्राथमिकता देते हैं। स्थानीय नेताओं के साथ सहयोग **(60%)** और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स **(BCs)** की भर्ती एवं प्रशिक्षण **(65%)** भी जागरूकता अभियानों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए, **55%** उत्तरदाता डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हैं, जबकि **50%** मोबाइल बैंकिंग वैन का उपयोग करते हैं।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

तालिका 3: बैंक अधिकारियों द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	आवृत्ति (%)
बुनियादी ढांचे की कमी (एटीएम, पीओएस)	65%
ग्रामीण निवासियों में डिजिटल साक्षरता की कमी	72%
उच्च परिचालन लागत	50%
दूरस्थ क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी	68%
नई प्रणालियों को अपनाने में अनिच्छा	40%

नीचे दी गई तालिका ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच को विस्तारित करने में आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं को दर्शाती है। ग्रामीण निवासियों की डिजिटल साक्षरता की कमी (**72%**) सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बाद दूरस्थ क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी (**68%**) और आवश्यक बुनियादी ढांचे (जैसे नकद काउंटर और एटीएम) की अनुपलब्धता (**65%**) प्रमुख चुनौतियाँ हैं। सर्वेक्षण में शामिल आधे प्रतिभागियों (**50%**) ने बताया कि उच्च परिचालन लागत एक बड़ी बाधा है, जबकि **40%** लोगों ने आधुनिक बैंकिंग प्रणालियों को अपनाने में अनिच्छा व्यक्त की।

तालिका 4: उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता

उठाया गया कदम	प्रति शाखा औसत नए खाते	प्रभावशीलता संतोष स्तर (%)
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम	150	70%
सरकारी योजना प्रचार (जैसे पीएमजेडीवाई)	200	85%
मोबाइल बैंकिंग वैन की तैनाती	100	60%
बिजनेस कॉरस्पोंडेंट (BCs) का प्रशिक्षण	120	75%

तालिका में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रति शाखा नए खातों की संख्या में वृद्धि और उनकी सफलता को दर्शाया गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार से प्रति शाखा औसतन 200 नए खाते खोले गए, जिससे 85% संतोष दर प्राप्त हुई। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के तहत 150 नए खाते खोले गए और इनकी संतोष दर 70% रही। मोबाइल बैंकिंग वैन की तैनाती से 100 नए खाते खुले, जिससे 60% संतुष्टि स्तर

दर्ज किया गया। वहीं, बिजनेस कॉरस्पोंडेंट (BCs) के प्रशिक्षण से 120 अतिरिक्त खाते खोले गए और इसकी संतोष दर 75% रही।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में ग्रामीण बैंकिंग के विस्तार का आधार वित्तीय समावेशन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल बैंकिंग समाधानों को बढ़ावा देना है। बैंकिंग प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने, दूरस्थ शाखाओं को प्रोत्साहन देने और तकनीक के उपयोग से वित्तीय अंतर को पाटा जा सकता है। सरकार की सहायता, वित्तीय साक्षरता पहल और समावेशी नीतियों के माध्यम से सतत विकास और ग्रामीण जनता का सशक्तिकरण संभव है। राज्य में पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए नीति-निर्माताओं, बैंकों और डिजिटल कंपनियों को मिलकर कार्य करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्वु, एडविन. (2020). क्या तकनीक ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन के बीच की खाई को पाट सकती है? *Technology Analysis & Strategic Management*, 33(1), 1-11. 10.1080/09537325.2020.1795111.

2. एलेसी, आर., और एंजेलुची, एम. (2014). वित्तीय समावेशन और महिलाओं के सशक्तिकरण: बचत खातों से प्राप्त साक्ष्य। *World Development*, 58, 179-193.

3. बगली, सुप्रवत और दत्ता, (2012). भारत में वित्तीय समावेशन का एक अध्ययन। *RADIX INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS & BUSINESS MANAGEMENT*, 1(8), 1-18.

4. फ्रे, सी. बी., एवं ओसबोर्न, एम. ए. (2017). रोजगार का भविष्य: कंप्यूटरीकरण से नौकरियां कितनी प्रभावित होंगी? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254-280.

5. हसन, एस., आलम, एम.एम., एवं रहमान, आर.ए. (2015). सूक्ष्म-वित्त के बाजार आकार का अनुमान: मलेशिया के सेलांगोर में शहरी सूक्ष्म उद्यमियों पर अध्ययन। *Asian Social Science*, 11(27), 269-274.

6. लुसार्दी, ए. (2014). वित्तीय साक्षरता: वित्तीय समावेशन का एक अनिवार्य घटक। *The World Bank Research Observer*, 29(2), 144-168.

7. मैज़ातुल, ए.के., आलम, एम.एम., और सईद, जे. (2016). मलेशिया के सार्वजनिक क्षेत्रों में सुशासन का अनुभवजन्य मूल्यांकन। *Economics & Sociology*, 9(4), 289-304.

8. मोल्ला, आर.आई., आलम, एम.एम., एवं वाहिद, ए.एन.एम. (2008). बांग्लादेश के सूक्ष्म-वित्त पर सवाल। *Challenge: The Magazine of Economic Affairs*, 51(6), 113-121.

9. मोर, नचिकेत और अनंत, बिंदु (2008). गरीबी को दूर करने के लिए वित्त और बाजारों तक पहुंच की रणनीति। *Development Outreach*, 10(2), 44-46.

10. रंजनी, केएस और बापट, वरदराज (2015). वित्तीय समावेशन को खाता खोलने से आगे बढ़ाना: बैंकों के लिए आगे का रास्ता। *Business Perspectives and Research*, 3(1), 52-65. 10.1177/2278533714551864.

11. राठी, मीनाक्षी एवं शर्मा, (2020). मध्य प्रदेश में औपचारिक ऋण के माध्यम से कृषि वृद्धि को प्रोत्साहित करना: वित्तीय समावेशन की दिशा में एक मार्ग। *BSSS Journal of Commerce.*

12. एहेर्ने, ए., प्रधान, एम., एवं टोरेली, एस. (2007). डिजिटल डिवाइड और वित्तीय समावेशन: नए युग के लिए नई नीतिगत दृष्टिकोण। *Information Technology for Development*, 13(2), 183-205.

13. त्रिपाठी, आशुतोष. (2013). भारत में स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम का प्रसार: संभावनाएं बनाम उपलब्धियां। *Journal of Asian and African Studies*, 49(1), 215-233.

14. वेंकटरामनी, शिवकुमार और भसीन, बलबीर। (2011). वित्तीय समावेशन का मार्ग: भारत में स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सफलता। *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 8(11). 10.19030/iber.v8i11.3181.